Journal of Socio-Educational & Cultural Research, Vol. 2, No. 5, July-December, 2016 ISSN : 2394-2878

भारतीय महिला उद्यमिता की समस्याएं
(पूर्वांचल के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ0 महबूब आलम*

सारांश

यह शोध–पत्र महिला उद्यमियों की समस्यों को समर्पित है। इस शोध–पत्र में पूर्वांचल की ग्रामीण महिला उद्यमियों के सन्दर्भ में अध्ययन किया गया है। इस शोध–पत्र में महिला सशक्तिकरण तथा सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है। पूर्वांचल में उद्यमिता का क्या स्थान तथा विशेषकर महिला उद्यमियों का जो गरीबी कम करने में कहा तक सहायक हो सकती हैं का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में महिला उद्यमियों की समस्याओं व उनके समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इसके लिए 200 शिक्षित महिलाओं से प्रश्नावली द्वारा उनके विचार जानने हेतु एक सर्वेक्षण किया गया है जिससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये हैं।

मुख्य शब्द : महिला, उद्यमियों, सशक्तिकरण, कुपोषण तथा असमानता।

परिचय (Introduction)

ऐसे क्षेत्रों में जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, किसी नये व्यक्ति/महिला के द्वारा उद्योग धन्धे स्थापित करने अथवा अन्य उद्योग व्यवसाय को प्रारम्भ करने में अदम्य साहस एवं उद्यमशीलता अथवा उद्यमिता की आवश्यकता होती है क्योकि ऐसे क्षेत्र में कच्चे माल के अभाव व तैयार माल के बिक्री की समस्याएं होती हैं। उद्यमिता के द्वारा बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण तथा असमानता जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। हमारे देश में भी अब उद्यमिता के विकास पर बल दिया जाने लगा है। अब तो महिला उद्यमिता विकास के द्वारा गरीबी, बेरोजगारी पर नियन्त्रण करने का प्रयास चल रहा है।

क्योकि इससे एक तरफ उद्यमी स्वयं रोजगार प्राप्त करता तथा दूसरी तरफ व अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उद्यमी शब्द का उद्‌गम फ्रेंच भाषा के शब्द 'एण्ट्रीपेण्ड्री' (Entrependre) से हुआ है, जिसका अर्थ है नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रमुख अभियाना (Expenditions) के लिए श्री रिचार्ड कैण्टीलोन ने अपने लेखन कार्य में किया था।

महिलाओं के महत्व को समझते हुए'' 11 दशक पूर्व ही स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर कहा था, ''औरतों की स्थिति में सुधार लाए बिना कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना।''

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए विभिन्न अध्ययन इस तथ्य का खुलासा करते हैं कि समाज में स्त्री–पुरूष समानता कम करने से अधिक आर्थिक समृद्धि आ सकती है और गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है। समाज में महिलाओं का दर्जा बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उपाय स्वरोजगार है। जिसके एक तरफ वे आय अर्जित करने में समर्थ होती हैं वहीं उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है जिसके फलस्वरूप वे संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रख सकती हैं। तमाम अवरोधों के बावजूद महिलाएं इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत ज्यादा सक्षम हो सकती हैं। एक प्रबन्धन के रूप में महिलाएं अपने घर को कितनी सफलतापूर्वक चला लेती हैं यह तो जगजाहिर है ही अतः यदि उनको उद्यमिता के क्षेत्र में विधिवत प्रशिक्षित कर दिया जाए तो उन्हें सक्षम होने से कोई रोक नहीं सकता।

* **एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर**

उद्यमी के सम्बन्ध में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक तथा अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार के विजेता मुहम्मद यूनूस का कथन है कि "Every Individual Is An Entrepreneur !"[1] "There is an entrepreneur within every human being."[2] इसके लिए यूनूस ने कुछ भिखारियों को धन देकर यह कहा कि तुम मांगने के साथ–साथ कुछ रोज के उपयोग होने वाले सामान जैसे– साबुन, तेल तथा पेस्ट आदि भी लोगों को बेचे। इस प्रकार कुछ दिन पश्चात वे भिखारी मांगना छोड़ दिये तथा अपना नया व्यवसाय करने में लग गये। इस प्रकार उनका यह प्रयोग सफल रहा कि ''प्रत्येक व्यक्ति एक उद्यमी है।''

अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. इस शोध–पत्र का उद्देश्य है महिला उद्यमिता पर प्रकाश डालना।
2. इस शोध–पत्र का उद्देश्य है महिला सशिक्त करण का मूल्यांकन करना।
3. इस शोध–पत्र का उद्देश्य है पूर्वांचल में महिला उद्यमिता का मूल्यांकन करना।
4. इस शोध–पत्र का उद्देश्य है महिला उद्यमियों की समस्याओं का पता लगाना तथा उनके समाधान हेतु सुझाव देना।
5. अन्य

परिकल्पना (Hypothesis)

इस शोध–पत्र की निम्न परिकल्पनाएं हैं –

1. इस अध्ययन की परिकल्पना है कि देश में महिला उद्यमिता विकास पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
2. इस अध्ययन की परिकल्पना है कि महिला उद्यमिता के विकास में पुरुष प्रधान समाज बाधक है।
3. इस अध्ययन की परिकल्पना है कि आज महिला उद्यमी अनेक समस्याओं रूपी जनजीर से जकड़ी हुई है।
4. इस अध्ययन की परिकल्पना है कि महिला उद्यमियों की भूमिका समाज में सार्थक है।
5. अन्य।

शोध प्रविधि (Research Methodology)

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समंक, दैवनिदर्शन द्वारा आज़मगढ़ जनपद का चयन कर प्राप्त किये गये हैं। निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु प्रतिशत एवं सहसम्बन्ध का उपयोग किया गया है।

तालिका नं0–1

भारत में साक्षरता दर : 1951–2011 (% में)

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	पुरुष–महिलाओं में अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.3	40.4	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्रोत : अर्थव्यवस्था अवलोकन, धनकर प्रकाशन मेरठ, जून 2011, P. 8

[1] The Economic Times, Lucknow, 27 Nov. 2007, P. 4
[2] Ibid

तालिका नं0–1 से स्पष्ट है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। वर्ष 1951 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः 27.16 प्रतिशत तथा 8.86 प्रतिशत थी। पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में अन्तर 18.30 प्रतिशत का था। वर्ष 2011 में पुरुष साक्षरता दर तथा महिला साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46 प्रतिशत पहुंच गई है तथा दोनों में 16.68 प्रतिशत का रह गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अब महिला साक्षरता दर का प्रतिशत धीरे–धीरे बढ़ रहा है लेकिन विश्व में महिला साक्षरता दर के प्रतिशत से अभी बहुत कम है।

तालिका नं0–2

पूर्वांचल में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

जनपद	कृषक	प्रतिशत	कृषि श्रमिक	प्रतिशत	कृषि में कुल लगे लोगों का प्रतिशत	पारिवारिक उद्योग	प्रतिशत	अन्य सेवाएं	प्रतिशत
आजमगढ़	540196	45.01	333457	27.79	72.80	94750	8.1	231441	19.17
मऊ	203586	33.96	158227	26.41	60.37	105104	17.5	132483	22.10
बलिया	239509	30.15	318446	40.08	70.23	42819	5.39	193661	24.38
जौनपुर	630138	51.84	249045	20.49	72.33	92671	9.62	243661	20.04
गाजीपुर	419879	44.04	263744	27.66	71.69	58983	6.19	210906	22.12
चंदौली	151625	28.74	188469	35.72	64.46	42380	8.03	145159	27.51
वाराणसी	207966	21.18	92573	9.43	30.61	221969	22.60	449850	45.76
मिर्जापुर	213957	29.93	237892	33.28	63.21	75490	10.56	187400	26.22
सोनभद्र	187133	34.79	206267	38.34	73.13	13380	4.49	131155	24.38
संत रविदास नगर(भदोही)	100244	25.79	58585	15.07	40.86	101116	26.02	128709	33.11

स्रोत :– उद्यमिता, भोपाल, फरवरी 2005, पृष्ठ–31.

किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां की 'व्यावसायिक जनसंख्या' विशेष भूमिका अदा करती है। व्यावसायिक संरचना में आते हैं किसान, कृषि मजदूर, पारिवारिक उद्योग व अन्य सेवाओं में लगे लोग। मूल रूप से कृषि पर आधारित पूर्वांचल अगर पिछड़ा है तो इसी संरचना में गड़बड़ी के चलते। वाराणसी व एक–दो अन्य को छोड़कर शेष जनपदों में यह संरचना काफी असंतुलित है। इसका सीधा असर इस क्षेत्र के विकास पर पड़ रहा है वहीं बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है।

आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि वाराणसी व भदोही को छोड़ शेष जनपदों यथा आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मीरजापुर व सोनभद्र की 60 फीसदी से भी अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। इन जनपदों की कुल व्यावसायिक जनसंख्या में से कृषि व्यवसाय में लगी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 72.81, 60.37, 70.13, 71.33, 71.69, 64.46, 63.31 व 73.13 है जबकि वाराणसी व भदोही में यह प्रतिशत क्रमशः 30.61 व 40.86 है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों जनपदों को छोड़ कर पूर्वांचल की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर है।

पारिवारिक व्यवसाय का अध्ययन करें तो आजमगढ़ में 8.9 प्रतिशत, मऊ में 17.53 प्रतिशत, बलिया में 5.39 प्रतिशत, जौनपुर में 7.62 प्रतिशत, गाजीपुर में 6.19 प्रतिशत, चंदौली में 8.03 प्रतिशत, वाराणसी में 22.6 प्रतिशत, भदोही में 26.02 प्रतिशत, मीरजापुर में 10.56 प्रतिशत और सोनभद्र में 2.49 प्रतिशत लोग इससे जुड़े है जबकि अन्य सेवाओं में कार्य करने वाले लोगों का प्रतिशतता क्रमशः 19.29, 22.10, 24.38, 20.04, 22.12, 27.51, 45.76, 33.12, 26.22 व 24.38 है। इस तरह स्पष्ट है कि वाराणसी को महानगर का दर्जा मिलने, शिक्षा का विस्तार होने तथा वाराणसी व भदोही में साड़ी व कालीन उद्योग

के विकास के चलते इन दोनों ही जनपदों में पारिवारिक उद्योग व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है जबकि पूर्वांचल के शेष जनपदों में इन व्यवसायों में कम जनसंख्या लगी हुई है। इस तरह उद्योगों के अभाव के चलते सम्पूर्ण पूर्वांचल क्षेत्र का आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ है। साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अगर इस क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना है तो इस क्षेत्र में अवस्थापनात्मक तत्वों की स्थापना कर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना होगा।

तालिका नं0–3

लिंगानुपात, महिला साक्षरता दर व उनकी औद्योगिक स्थिति : पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश)

क्र0सं0	जिला	लिंगानुपात	महिला	सम्पूर्ण जनसंख्या से साक्षरता दर (%) में औद्यो0रोज0 का (%)
1.	आज़मगढ़	1026	72.44	0.11
2.	जौनपुर	1021	43.53	0.02
3.	देवरिया	1003	43.56	0.24
4.	मऊ	984	50.86	–
5.	प्रतापगढ़	983	42.63	0.06
6.	सुल्तानपुर	980	41.81	0.01
7.	संत कबीरनगर	978	35.45	–
8.	अम्बेडकर नगर	977	45.98	–
9.	गाजीपुर	974	44.39	0.09
10.	कुशीनगर	961	30.85	–
11.	गोरखपुर	959	44.48	0.45
12.	बलिया	952	43.92	.002
13.	सिद्धार्थनगर	946	28.35	–
14.	फैजाबाद	940	43.35	0.13
15.	महाराजगंज	933	28.64	–
16.	चंदौली	922	45.45	–
17.	संत रविदास नगर	918	35.45	–
18.	बस्ती	916	39.00	0.09
19.	वाराणसी	908	48.59	0.50
20.	गोण्डा	899	27.29	0.10
21.	मिर्जापुर	897	39.80	0.73
22.	सोनभद्र	896	34.26	–
23.	बलरामपुर	896	21.58	–
24.	इलाहाबाद	882	46.61	0.67
25.	बहराइच	865	23.27	0.05
26.	श्रावस्ती	859	18.75	–
	पूर्वी उत्तर प्रदेश	**941**	**–**	**0.16**
	उत्तर प्रदेश	**898**	**42.98**	**0.53**

स्रोत– जनगणना–2001 * प्रादेशिक नियोजन भूगोल–MB Singh

ऐसी परिस्थिति में जब देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी (48.27 प्रतिशत) है, महिलाओं को आर्थिक विकास की प्रक्रिया से पीछे छोड़, देश को सुदृढ़ आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। भारतीय महिलाओं में खालीपन की भावना, निराशा, घुटन और स्वावलम्बन की चाह के बीच यह भावना कि ''हम कुछ नहीं करते'' न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार, समाज और देश के लिए भी घातक है। स्वावलम्बन की बढ़ती चाह को उनकी शिक्षा, सामर्थ्य, रूचि और परिवेश के अनुरूप पहचान कर समुचित उद्योग की स्थापना द्वारा महिलाओं को आर्थिक सफलता और सामाजिक बराबरी प्रदान की जा सकती है। एक उद्यमी महिला पारिवारिक और समाज हित में लिए जाने वाले निर्णयों में अहम् भूमिका निभाती है साथ ही अपने विकास की दशा एवं दिशा स्वयं निर्धारित करती है।

पूर्वांचल $23^{0}45$ उत्तरी से $28^{0}30$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}45$ 'पूर्वी देशान्तर से $84^{0}30$' पूर्वी देशान्तर के मध्य 85.844 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल पर विस्तृत है। सम्पूर्ण पूर्वांचल प्रमुखतः एक मैदानी क्षेत्र है। यह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से विपन्न है। ओबरा, रेनुकुट, शक्तिनगर तथा सिंगरौली, प्रमुख तापीय और जल विद्युत उत्पाद केन्द्र हैं। पूर्वांचल क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा 80 प्रतिशत जनसंख्या पूर्णतः कृषि पर आधारित है। कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पूर्वांचल की कुल जनसंख्या 605.36 लाख (वर्ष 2001) है जिसमें 311.88 लाख पुरूष तथा 293.48 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं। पूर्वांचल के विकास की मुख्य धारा में पूर्वांचल को महिलाओं के जोड़े बिना यहाँ के विकास की कल्पना भी अधूरी है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर आनुभविक, तुलनात्मक और मानचित्रण विधि से पूर्वांचल में जिला स्तर पर महिलाओं की आनुपातिक संख्या, साक्षरता दर और विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों में भागीदारी का वितरण स्पष्ट करते हुए महिलाओं में औद्योगिक सहभागिता में कमी के कारणों पर प्रकाश डाला गया है साथ ही पूर्वांचल में उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। पूर्वांचल में महिलाओं से सम्बंधित विधि विशेषताओं का विवरण तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में लिंगानुपात 898 है जबकि पूर्वांचल में यह अनुपात 941 है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की अपेक्षा पूर्वांचल में महिलाओं की अधिक भागीदारी प्रकट करता है। पूर्वांचल के 26 में से 14 जिलों में राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात मिलता है। लिंगानुपात की दृष्टि से आजमगढ़, मऊ और देवरिया सबसे महत्वपूर्ण जनपद हैं।

विकास हेतु साक्षरता के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है, परन्तु पूर्वांचल में साक्षरता का स्तर न्यून है। जहां देश की औसत साक्षरता 52 प्रतिशत है वहीं पूर्वांचल में इसका स्तर मात्र 32 प्रतिशत है। पूर्वांचल में 12 जनपदों में महिला साक्षरता दर प्रदेश में महिला साक्षरता दर से अधिक मिलती है। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से पूर्वांचल में आजमगढ़ जनपद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल में 14 जनपदों में महिला साक्षरता की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। यहाँ महिला सशक्तीकरण हेतु पहला कदम साक्षरता की दर का बढ़ना है। महिलाओं में साक्षरता का स्तर बढ़ने से न कवल उनके आत्मविश्वास, सामर्थ्य और शोषण के विरूद्ध बल मिलेगा बल्कि सामाजिक–आर्थिक कार्यों में, उनकी निपुणता और दक्षता भी बढ़ेगी।

सम्पूर्ण जनसंख्या की दृष्टि से औद्योगिक रोजगार संबंधी प्रतिशत के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्वांचल में सम्पूर्ण जनसंख्या से औद्योगिक रोजगार का प्रतिशत मात्र 0.16 है। जिला स्तर पर सम्पूर्ण जनसंख्या से औद्योगिक रोजगार के प्रतिशत में व्यापक असमानता मिलती है। क्षेत्र में सम्पूर्ण जनसंख्या में औद्योगिक रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत सम्पूर्ण रोजगार का मात्र 8 से 10 प्रतिशत के बीच मिलता है। पूर्वांचल में महिलाओं की औद्योगिक रोजगार में निम्न भागीदारी के लिए यहाँ की सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक तथा निम्न आर्थिक दशा उत्तरदायी है। पूर्वांचल की जातीय संरचना के

अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग–धंधे में स्त्रियों के कार्य को हतोत्साहित करते हैं। इसलिए यहाँ कृषि के साथ औद्योगिक उत्पादकता और भी न्यून है।

औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की 65.11 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद पूर्वांचल में सिर्फ 11.62 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयाँ और 17.67 प्रतिशत रोगार की स्थित हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में 100 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर औसतन 2 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं वहीं पूर्वांचल में एक से भी कम इकाई पाई जाती है। औद्योगिक इकाइयों की कम संख्या भी औद्योगिक कार्य हेतु महिलाओं के अवसर को घटा देती है।

खनिज संसाधन की दृष्टि से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में हस्तकला, शिल्पकला जैसे कुटीर इकाइयाँ कुश्ला संरक्षण के अभाव में समाप्त हो रही हैं। वाराणसी, मऊ तथा मुबारकपुर की रेशमी साड़ियाँ, पीतल के बर्तन, काष्ठ उद्योग, जौनपुर का सुगन्धित इत्र, मिर्जापुर और भदोही का कालीन उद्योग, चुनार का मिट्टी बर्तन उद्योग, निजामबाद के काली मिट्टी के विश्व विख्यात सामान आज भी महिलाओं के स्वावलम्बन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। पूर्वांचल में खनिज, कृषि और माँग पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की व्यापक सम्भावनाएँ मौजूद हैं जिनके संचालन में महिलाओं की अहम् भूमिका है। इसके अतिरिक्त – डेयरी, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई–कढ़ाई और छपाई इत्यादि उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ भी मौजूद हैं जिनमें हल्के प्रशिक्षण के उपरान्त महिला उद्यमियों को प्रवेश और कुशलता प्रदान की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि विकास की मुख्य धारा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जा सके। इन्हीं योजनाओं में महिला डेयरी परियोजना, इंदिरा महिला योजना, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना, वृद्धावस्था एवं मातृत्व लाभ योजना, बालिका समृद्धि योजना, न्यू मॉडल चर्खा योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना इत्यादि प्रमुख हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं को कृषि और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों, उद्योगों, सेवाओं और व्यापार के क्षेत्र में उन्हें अपना कार्य शुरू करने हेतु पूँजी और आवश्यक कुशलता विकसित करने हेतु प्रौद्योगिक संबंधित प्रशिक्षण द्वारा रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और परिवार की आय बढ़ाने में अहम् भूमिका अदा कर सकें। इन योजनाओं का लक्ष्य सामाजिक स्तर पर महिलाओं की बराबरी के लिए आर्थिक एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उनके संवैधानिक अधिकारों एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागृत करना भी है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पूर्वांचल की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी अहम् है, परन्तु महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न है साथ ही यहाँ औद्योगिक कार्यों हेतु आवश्यक प्रौद्योगिक के प्रशिक्षण और पूँजी का अभाव है। यहाँ की सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था भी कृषि और औद्योगिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती है। महिलाओं की सृजनात्मक शक्ति, घुटन, अकेलापन और निराशा के भँवर में फँस चुकी है। फिर भी महिलाओं में स्वावलम्बन की प्रबल चाह है, जिसे आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार विश्लेषित कर संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप सही व्यवसाय के चयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो महिलाओं को सामाजिक स्तर पर बराबरी और सुदृढ़ विकास हेतु उनमें आत्मबल, विश्वास और उन्नत विचार कायम करेगा।

महिला उद्यमियों की समस्याएं

सरकार ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिला उद्यमियों व कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं व नीतियां बनाई है। लेकिन महिला उद्यमियों के सामने अनेक प्रमुख

समस्याएं दीवार बनकर खड़ी हैं। वैसे भी यह क्षेत्र महिलाओं से सम्बन्धित होने के कारण जैसे एक तो महिला तथा दूसरे गरीब अर्थात दो तरह से कमजोर होने के कारण समस्याएं गम्भीर हो जाती हैं। प्रमुख समस्याएं निम्न हैं :–

1. कच्चे माल की समस्या
2. वित्त के अभाव की समस्या
3. शिक्षा तथा साक्षरता के अभाव की समस्या
4. तकनीक के अभाव की समस्या
5. विपणन की समस्या
6. प्रशिक्षण के अभाव की समस्या
7. प्रबन्ध व कौशल के अभाव की समस्या
8. बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या
9. सूचना व परामर्श के अभाव की समस्या
10. पुरुष प्रधान समाज के शोषण की समस्या
11. गुणवत्ता के अभाव की समस्या
12. विद्युत की आपूर्ति की समस्या
13. मूलभूत सुविधाओं के अभाव की समस्या
14. पारिवारिक असंतोष की समस्या
15. लेखांकन व वित्त के ज्ञान के अभाव की समस्या

आज एक प्रश्न सामने आ रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम सफल क्यों है? इसका उत्तर यह है कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों से अलग है। यह उनके लिए अतिरिक्त समस्याओं को आमन्त्रित करती है। ये समस्याएं निम्न रूप में हो सकती हैं :–

1. गतिशीलता की समस्या (Problem of Mobility)
2. अपने आप निर्णय लेने की क्षमता के अभाव की समस्या
3. वर्तमान व्यवसाय व्यवस्थाओं/आचार–व्यवहार के साथ समझौता न कर पाना (Inability to Cope up with Present day Business Practices)
4. भारतीय महिला उद्यमी की सर्वप्रमुख अड़चन–भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता की समस्या
5. अधिकांश सासों द्वारा महिला उद्यमी को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने की समस्या
6. उद्योग/व्यवसाय में पूरा समय नहीं दे पाने की समस्या

पूर्वांचल के आजमगढ़ जनपद में 20 से 25 वर्ष को शिक्षित ग्रामीण स्त्रियों के सर्वेक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष सामने आये हैं :–

(1) 72 प्रतिशत स्त्रियों सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहती हैं तथा स्वरोजगार क्षेत्र 8 प्रतिशत स्त्रियाँ अपना लगाव बताती है 12 प्रतिशत स्त्रियाँ किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता कि आज स्त्रियाँ रोजगार प्राप्त करने की इच्छुक हैं अर्थात इनकी मानसिकता अब घर की चाहरदीवारी से बाहर निकलने की हो गई है, जो महिला सशक्तिकरण एवं महिला उद्यमिता के विकास के लिए एक अच्छा संकेत है।

(2) सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि 52 प्रतिशत स्त्रियां उद्यमिता विचार से परिचित थी।

(3) सभी युवा महिलाओं का मत था कि महिलाएं सफल उद्यमी बन सकती हैं।

(4) 92 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार व पति का सहयोग मिलने पर उद्यमिता से जुड़ने की इच्छा जाहिर किये थी।

(5) 98 प्रतिशत महिलाओं प्रशिक्षण मिलने पर उससे जुड़ने के लिए तत्पर रही हैं।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस सर्वेक्षण से कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये है। सर्वप्रथम यह कि शिक्षित ग्रामीण युवा महिलायें अब जागरूक हो रही है रोजगार मिलने पर किसी क्षेत्र चाहे वह सरकारी, निजी या स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक हैं। अधिकांश ने महिला उद्यमिता से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है अर्थात महिला उद्यमिता की पक्षधर हैं। अधिकांश महिलाओं ने लोकलाज के भय, प्रशिक्षण का अभाव, पूँजी का अभाव, परिवार के सहयोग के अभाव तथा पुरुष प्रधान समाज का होना आदि को महिला उद्यमिता के विकास में बाधा माना है। इस सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि यदि महिलाओं को रोजगारपरक शिक्षा दी जाए, इनमें चेतना व विश्वास पैदा किया जाए पुरुष प्रधान की सोच में परिवर्तन लाया जाए तथा महिला सहभागिता के विचार को व्यवहार में लाया जाए तो अपने देश की महिलाएं उद्यमिता से जुड़कर गरीबी बेरोजगारी को कम करने में सार्थक सिद्ध होगी। आन्ध्र प्रदेश की गॉव की एक प्रधान के रूप में क्रांतिवादी का नाम बहुत ही पहले प्रकाश में आ चुका है तथा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से अवार्ड भी मिल चुका है लेकिन आज भी देश में महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

''महिला आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय की दो सौ लड़कियों पर एक अध्ययन कराया जिससे यह पता चला कि 91.7 प्रतिशत लड़कियां कैम्पस में यौन उत्पीड़न का शिकार बनी हैं। शिक्षित लड़कियों के साथ दिल्ली जैसे शहर में इतनी अधिक संख्या में यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध का होना भारतीय समाज और प्रशासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का अंदाजा लगाया जा सकता है।''[3]

''शिक्षा वह प्रकाश है, जिसके द्वारा अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। गुननार मिर्डल के कथानुसार साक्षरता संसार का मार्ग प्रशस्त करती है अन्यथा वह बन्द पड़े रहते हैं। यह किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। नारी की शिक्षा एवं उसके शोषण का सीधा सम्बंध है। हेनरी बेरो ब्रोधन के अनुसार शिक्षा लोगों का नेतृत्व सरल बनाती है, लेकिन उन्हें हांकना कठिन, उन पर शासन करना सरल बनाती है लेकिन उन्हें गुलाम बनाना असंभव है।''[4]

पिछले दो दशकों में ऐसे काम बढ़े हैं। आर्थिक जरूरतों के चलते औरतें घर से बाहर जाकर काम करने को प्राथमिकता दे रही हैं, इसके बावजूद उन्हें परिवार के कार्यों से मुक्ति मिलती हो, ऐसा नहीं है। भारत का ही उदाहरण लें, तो एक ओर जहां स्त्री को आर्थिक स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सदियों से चली आ रही परंपरागत जिम्मेदारियों को निभाने की सीख भी दी जाती है।

इन्हीं संस्कार–गुणों और उन्हें निर्धारित करने वाली मातृत्व–शक्ति को परखते हुए, स्वामी विवेकानन्द ने मां का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया था। उन्होंने कहा, ''आप मुझे केवल सौ अच्छी माताएं दे दीजिए, मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा।''

आज भी उनका कथन व्यवहारिक व सत्य सिद्ध हो रहा है। यदि हम महिलाओं में शिक्षा व समानता का आदर करे तो महिलाएं एक अच्छी माँ के साथ सफल उद्यमी बनकर गरीबी बेरोजगारी, कुपोषण तथा आर्थिक असमानता को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं।

वस्तुतः किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सही पैमाना यह है कि राष्ट्र की महिलाओं ने क्या प्रगति की है और उनके समाज में नारी का क्या स्थान है, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। संभवतः इसी से संस्कृत में कहा जाता है : ***''यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते–रमन्ते तत्र देवता''***

---

[3] कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, नवम्बर 2001, पृष्ठ–14.

[4] कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली, मार्च 2005, पृष्ठ–7.

निष्कर्ष (Conclusion)

अन्त में निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते है कि भारतीय महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किया है उसका पूर्ण लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। आज भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता वैसी ही है जैसे पहली थी। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देश में अब तक उचित वातावरण नहीं बन पाया है। महिला उद्यमी एक तरफ तो व्यवसाय से सम्बन्धित समस्याओं का सामना कर रही है तथा दूसरी तरफ एक महिला होने के नाते दूसरी समस्याओं का सामना कर रही है। महिला उद्यमी आज अनेकों अवरोधों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। हां यह अवश्य है कि महिला साक्षरता व शिक्षा के विकास के साथ–साथ इनके लिए थोड़ा अवसर अवश्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इसी को सफलता मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। आज की महिला उद्यमी के सामने व्यवसाय से सम्बन्धित प्रमुख समस्या इस प्रकार है –

1. कच्चे माल के अभाव की समस्या, 2. वित्त या ऋण या कार्यशील पूँजी के अभाव की समस्या, 3. शिक्षा तथा साक्षरता के अभाव की समस्या, 4. तकनीक के अभाव की समस्या, 5. विपणन से सम्बन्धित समस्या, 6. प्रशिक्षण के अभाव की समस्या, 7. प्रबन्ध, कौशल तथा सही निर्णय न ले पाने की समस्या, 8. बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता की समस्या, 9. पुरुष प्रधान समाज के शोषण की समस्या, 10. सूचना व परामर्श के अभाव की समस्या, 11. गुणवत्ता के अभाव की समस्या, 12. मूलभूत सुविधाओं के अभाव की समस्या, 13. लेखांकन व वित्त ज्ञान के अभाव की समस्या, 14. अन्य।

इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों को महिला होने के कारण कुछ अन्य विशेष समस्याओं का भी सामना करना पड़ता जो अग्र हैं – 1. गतिशीलता की समस्या, 2. अपने आप निर्णय न ले पाने की समस्या, 3. वर्तमान व्यवसाय व्यवस्थाओं के साथ समझौता न कर पाने की समस्या, 4. भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता की समस्या, 5. परिारिक कलह की समस्या, 6. उद्योग/व्यवसाय में पूरा समय नहीं दे पाने की समस्या आदि।

उपरोक्त समस्याएं देश को ग्रामीण महिला उद्यमियों पर अधिक लागू होती हैं। पूर्वांचल तो उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा भाग है। यहाँ पर तो बड़े उद्योग, मझोले उद्योग केवल नाममात्र के हैं। यहाँ पर वाराणसी को छोड़कर शेष अनय जनपदों में उद्योगों की दशा शून्य है। पूर्वांचल में महिला उद्यमियों की दशा और भी खराब है इसके पीछे यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं।

पूर्वांचल में कुटीर उद्योग तथा कृषि पर आधारित कुछ औद्योगिक इकाइयां अवश्य कर रही हैं। पूर्वांचल में स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार के अन्तर्गत महिलाएं स्वरोजगार हेतु कुछ कुटीर उद्योगों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं। पूर्वांचल में औद्योगिकरण न होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि यहाँ उद्यमिता के विकास हेतु वातावरण नहीं है तथा सरकार के भी सहयोग का अभाव होना एक मुख्य कारण है। किसी शक्तिशाली राजनेता का न होना। यहां पर उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी इसके पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है।

यदि पूर्वांचल में आर्थिक समृद्धि लाना है तो क्षेत्र की महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, पुत्र तथा पुत्रियों में भेद न कर महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार प्रदान कर विकास में उनकी सहभागिता प्राप्त की जा सकती है तथा गरीबी, बेरोजगारी तथा कुपोशण व असमानता की समस्याओं पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

अन्त में हम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते है कि महिलाओं के विकास के बिना किसी देश व समाज का विकास सम्भव नीं है नारी सहभागिता के बिना ग्रामीण विकास का स्वप्न अधूरा है। हमारे देश में अब तक जो ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है उसका मुख्य कारण नारी के विकास व सहभागिता को नकारना है। आज देश में नारी की स्थिति अत्यन्त भयावह है। आज समाचार पत्रों में यह खबर छपती है कि नारी को पुरूष के समान अधिकार प्राप्त है। परन्तु क्या ये कथन व्यवहार के धरातल

पर सच है ? नहीं। वास्तविकता यह है कि नारी समाज का एक अहम हिस्सा है किन्तु इसकी सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक भूमिका शून्य है। हमारा पुरूष प्रधान समाज है इसमें महिलाएं विभिनन प्रकार से प्रताड़ित की जाती है। मुंशी प्रेमचन्द ने ठीक ही कहा है कि इस पुरूष प्रधान समाज में ''जब नर में नारी के गुण आ जाये तो वह महात्मा बन जाता है और नारी में जब नर के गुण आ जाये तो वह कुलटा हो जाती है।'' समाज में जितनी भी बाधाएं है वह नारी हेतु है पुरूषों को पूरी छूट है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित है, बेरोजगार है तथा उनका स्वास्थ्य भी घटिया स्तर का है। हमारे देश में लड़की पैदा होने पर लोक शोक का भाव प्रकट करते है, शिशु भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। देश में पुत्रों के प्रति अधिक आकर्षण है क्योंकि वह वृद्ध अवस्था में सहारा बनेगा। इस सोच को बदलना होगा क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं कि लड़का ही सहारा बनेगा और लड़की नहीं। इसके विपरीत ही होता है। शेक्सपीयर ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि "Son is son till the marrige and daughter is daughter till the death" अर्थात् लड़का जब तक लड़का है जब तक उसका विवाह न हो जाय तथा लड़की तब लड़की रहेगी जब तक वह मर न जाए। महिलाएं खास कर गरीब महिलाएं वित्तीय प्रबन्धन में पुरूषों से अधिक कुशल, ईमानदार और जवाबदेह होती है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता स्वीकार करके ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है तथा गरीबी उन्मूलन को सफल बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference) :

1. Dr. H.D. Dwarakanath, Rural Credit and Women Self Help Groups - A Profile of Ranga Reddy District in Andhra Pradesh, Kurukshetra, New Delhi, Nov. 2002, Pp. 9-15.
2. Dr. P. Loganathan and R. Asokan, Inter Regional Development of Self Help Groups in India, Kurukshetra, New Delhi, March 2009, Pp. 9-12.
3. H.S. Shylendra, Role of Self Help Groups, Yojan, New Delhi, Jan. 2008, Pp. 25-28.
4. Prasant Sarangi, Self Help Groups - An Experiment in Orissa, Kurukshetra, New Delhi, Feb. 2003, Pp. 30-32.
5. R.K. Ojha, Self Help Groups and Rural Employment, Yojana, Ministry of Information and broad casting, New Delhi, May, 2001, Pp. 20-23.
6. Rimjhim Mousumi Das, Microfinance Through SHGs - An boon for the rural poor, Kurukshetra, New Delhi, Feb. 2004, Pp. 43-45.
7. Sabyasschi Das, Self Help Groups and Micro credit-Synergic Integration, Kurukshetra, New Delhi, Aug. 2003, Pp. 25-29.
8. मेघा दुभाशी, माइक्रो उधम और एसएचजी–एक रूडा अनुभव, योजना नई दिल्ली, फरवरी 2005, पेज – 39–41.